

## वाइब्रेंट वल्लिज के नवासियों को दो घर देने की तैयारी

### चर्चा में क्यों?

28 मई, 2023 को उत्तराखण्ड में वाइब्रेंट वल्लिज कार्यक्रम की नोडल अधिकारी नतिका खंडेलवाल ने बताया कि प्रदेश के चार वाइब्रेंट वल्लिज के नवासियों को सीजनल माइग्रेशन वाले स्थानों पर भी राज्य सरकार घर बनाकर देने की तैयारी कर रही है। इसके लिये हाल ही में मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये गए।

### प्रमुख बिंदु

- वदिति है कि हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमति शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्देश मिले हैं कि वाइब्रेंट वल्लिज कार्यक्रम के तहत हर गाँव की विशेषता को देखते हुए तीन माह के भीतर एक्शन प्लान तैयार किया जाए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट वल्लिज कार्यक्रम में प्रदेश के चार सीमांत गाँव नीति, माणा, मलारी और गूंजी शामिल हैं।
- वाइब्रेंट वल्लिज कार्यक्रम के तहत हर गाँव के ऐसे परिवारों को दोनों स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास दिया जाएगा। इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी।
- वही, ये भी तय हुआ है कि जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में वाइब्रेंट वल्लिज कार्यक्रम की जनपद स्तरीय समिति और फरि खंड स्तरीय समिति गठित होगी।
- वाइब्रेंट वल्लिज में रहने वाले लोगों से फल, सब्जियाँ, दूध, अंडे, मीट आदि सामग्री को सीमा सुरक्षा बल खरीदेंगे। इसके लिये भी एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जसि जल्द ही हाई पावर कमेटी को भेजा जाएगा।
- अगर किसी गाँव का सेना या सुरक्षा बलों के साथ कोई समस्या या मुद्दा है तो इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजना होगा। हर वाइब्रेंट वल्लिज में एक ग्रोथ सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। आईटीबीपी ने भी सभी वाइब्रेंट वल्लिज के लिये अपना एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
- मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने निर्देश दिये हैं कि जिन वाइब्रेंट वल्लिज में सार्वजनिक परिवहन की समस्या है, वहाँ मनी बस का संचालन किया जाएगा। इसके लिये संबंधित जिले से प्रस्ताव परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
- भूमि अधिकारों से संबंधित समस्याओं का सभी जिले राजस्व विभाग के साथ समन्वय बनाकर तत्काल समाधान करेंगे। वाइब्रेंट वल्लिज में टेली मेडिसिनि की सुविधा भी दी जाएगी।